facilities are created in every urban local body and then sewage treatment plants (STPs) are set up in various municipal bodies so that this problem can be taken care of. As I told you, Sir, again, this has to be done by the urban local bodies. We, the Government of India, are trying to guide the States and also finance the schemes for sewerage treatment plants through our mission.

Scarcity of water in DIZ area

*243. ANIL KUMAR SAHANI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether drinking water is being supplied through a single pipeline for water tank and quarters in DIZ Area, Sector-4, Gole Market;

(b) if so, whether due to single pipeline, water can either be stored in water tank or water can be used in quarters resulting in hardship and water shortage to residents;

(c) if so, whether there is urgent need for two separate pipelines for water supply to both the water tank and quarters; and

(d) if so, the steps taken/being taken by the NDMC/CPWD in this regard?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Through a single pipeline, water is being stored in individual terrace water tanks of 500 litres capacity for each quarter and is also supplied directly in the quarters. This single pipeline enables storage of water in individual overhead tanks as well as usage inside the quarters.

(c) Technically, there is no requirement for two separate pipelines for supply of water to individual terrace water tanks and for direct supply inside the house. Since the availability of water is limited and therefore this system ensures equitable distribution of water at each quarter.

(d) No action required in view of reply at (c) above.

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, I have a request to make. How can Parliament ponder over this issue?

MR. CHAIRMAN: Make the suggestion to the hon. Minister.

SHRI RAJEEV SHUKLA: It says how water is being supplied to Sector — 4, Gole Market.

श्री सभापति : आप सज़ेशन दे दीजिए।

डा. अनिल कुमार साहनी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली के गोल मार्केट एरिया में जो पाइप लाइन लगाई गई है, वह एक ही पाइप लाइन लगी है। जो लोग नीचे रहते हैं और ऊपर की स्टोरी में, ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, उनके लिए एक ही पाइप से पानी जाता है। आपने अपने उत्तर में बताया है कि उनके लिए हरेक को अपनी टंकी में 500 लीटर पानी भरने की लिमिट है, लेकिन जब नीचे वाला स्नान करने लगता है तो ऊपर पानी भरता ही नहीं है और आपने यह भी सीमित किया हुआ है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही पानी मिलेगा। जब नीचे वाले स्नान करके पूजा करने लग जाते हैं, तब तक ऊपर वाले का पानी ही नहीं भरता है। इससे पानी की बहुत किल्लत होती है।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

डा. अनिल कुमार साहनी : यह सवाल ही है, सर। हमारा सवाल यह है कि पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। खासकर के दिल्ली में, खाली गोल मार्केट की ही बात नहीं है, दिल्ली की अन्य पूरी जगहों पर पानी की किल्लत है। गोल मार्केट सेक्टर 4 के लोग हमें आकर मिले थे। मैंने उन्हें कहा था कि इस बात को हम हाउस में उठा देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां दो पाइप लाइन लगाने की व्यवस्था करेंगे, ताकि डायरेक्ट पानी ऊपर वाले की टंकी में भी जाए और नीचे नहाने वाले भी मिले, यानी नीचे भी मिले और ऊपर भी मिले? इस बारे में हम जानना चाहते हैं।

श्री एम. वेंकैया नायडु : चेयरमैन सर, दो पाइप लाइन लगाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या यह है कि जितना पानी चाहिए, उतना पानी उपलब्ध नहीं है। इस कारण से यह सब हो रहा है, जैसा मैंने बताया है। यहां डिमांड और सप्लाई में अंतर है। सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जितना पानी है, उतना पानी ही हम सप्लाई कर पा रहे हैं। इसमें और वृद्धि करने के लिए कोशिश चल रही है। आने वाले दिनों में हम इस दिशा में और भी प्रयास करेंगे। सभापति जी, मैं कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करना चाहता हूं, जैसा हमारे शुक्ल जी ने कहा। The question is related to one particular colony in one city. This has to be kept in mind.

डा. अनिल कुमार साहनी : सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय यह व्यवस्था केवल गोल मार्केट एरिया में ही करने जा रहे हैं, या पूरी दिल्ली में करने जा रहे हैं? वे इसका हमें जवाब दे दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल : आप अधिकारियों को कह दीजिए। ...(**व्यवधान**)... समस्या का समाधान हो जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : नहीं, नहीं। नरेश जी, बैठ जाइए। प्लीज, प्लीज।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am willing to discuss each individual case with hon. Members. What I told applies to the entire Delhi. This particular area is supposed

to be the so-called VIP Lutyens' Zone. Everything is there in this area. That may be the reason for focussing more attention on this issue. But I can assure the House that the Government of India, in consultation with the NDMC and also the local bodies, is trying to improve water supply. Sir, 500 litres of water is available to them because the tank is of that capacity. We are trying to give water two times a day.

श्री विजय गोयल : सभापति महोदय, यह प्रश्न इसलिए उठा है कि दिल्ली में पानी की समस्या विकराल है, जैसा मंत्री जी ने भी माना है कि पानी की शॉर्टेज है। उसके अलावा पानी की लीकेज है, पानी की वेस्टेज है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली जल बोर्ड जो एन.डी.एम.सी., सी.पी.डब्ल्यू.डी. क्षेत्र को 28 एम.जी.डी. पानी देती है, उसमें कितने पानी की बिलिंग होती है और बाकी जो पानी वेस्ट जा रहा है, लीकेज में जा रहा है, चोरी हो रही है, उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं?

श्री एम. वेंकैया नायडु : सभापति महोदय, कितनी बिलिंग हो रही है, वह जानकारी अभी मेरे पास तुरंत अवेलेबल नहीं है, मगर उसे इक्ट्ठा करके मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा। साथ ही, जो पानी बेकार जाता है, उसको रोकने के लिए अलग-अलग उपाय हैं, उनसे भी मैं सदस्य को अवगत करा दूंगा।

श्री परवेज़ हाशमी : चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन फ्लैट्स का जिक्र है, इसमें गोल मार्केट का जिक्र किया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि स्पेशली गर्मियों में चार-चार महीने तक पानी नहीं मिलता है। पानी एक दिन आता है, फिर एक हफ्ते नहीं आता है, लेकिन उसका बिल पूरा आता है। यहां कर्मचारी रहते हैं, सब government employees हैं। उनकी सैलेरी से बिल तो पूरा जाता है, लेकिन पानी उन्हें नहीं मिलता है, तो क्या गवर्नमेंट इसका भी कोई प्रोविजन करेगी कि जहां पर तीन-तीन, चार-चार महीने तक पानी नहीं दे पाते, लेकिन उनके बिल पूरे आते हैं, तो उसको चैक किया जाए और उसमें उनको कोई रिलीफ मिले?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Chairman, Sir, the CPWD has been asked to replace the pipelines which are old and rusted and also to provide more water to those areas. But, they say that water is being made available by NDMC and NDMC is under a different Ministry. ...*(Interruptions)*...

श्री परवेज़ हाशमी : सर, एन.डी.एम.सी. सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है।

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। एक मिनट सुन लीजिए।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We are in touch with the Home Ministry also on this issue. Sir, in March, 2014, 6,12,100 litres were daily supplied; in April, 5,31,670 litres were supplied; in May, 6,26,000 litres were supplied; and in June, 7,73,000 litres were supplied. Sir, the demand is around ten lakh litres; the supply is around seven lakh litres. That gap is there. What the hon. Member said is a fact. They are not getting adequate water supply. With regard to the issue that the hon. Member has raised that billing is done even without supply of water, I will definitely look into that issue.

श्री ए.यू. सिंह दिव : सर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि पानी की कमी है, इसलिए हम गोल मार्केट में पानी सप्लाई नहीं कर सकते। मैं मंत्री जी से आपके थ्रू यह पूछना चाहूंगा कि In all foreign countries, the sea water is converted into drinking water and this kind of a thing should also be done in India. तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम है, जो सी वॉटर को ड्रिंकिंग वॉटर में कन्वर्ट करे और गोल मार्केट और दूसरी जगहों में पानी सप्लाई कर सके?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सी वॉटर को यहां लाएंगे दिल्ली में?

श्री सभापति : आपको समुद्र को यहां लाना होना।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I can understand the concern of the hon. Member. Sir, not only this hon. Member, there is a concern throughout the country because groundwater has been depleting day by day. Rains have also become scarce. Water availability is becoming a major problem. It is a major challenge before the country. One solution is conserving the rain water. Second is avoiding wastage of water, and the third one is, as suggested by the hon. Member, desalination plants. Desalination is one solution, but comparatively, the cost is a little high. As of now, we have one project that has been taken up by the Tamil Nadu Government with the support of the Ministry of Urban Development. In Chennai, 100 MLD desalination drinking water plant has been set up. Such schemes can be taken up by States where sea is nearer, but it cannot be taken up in Delhi because we don't have sea here.

Expediting environment clearances

*244. SHRI KALPATARU DAS: Will the Minister of ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether it is proposed to expedite environment clearances to ensure early execution of such projects pending since long, if so, the details thereof;

(b) whether the above measures would help to ensure fast development of SEZ sector; and

(c) the status to ensure fast execution of road projects in the naxal areas which have been held up on account of environment and other various reasons?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.